

जनजातियों के शिक्षा हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

शोध-निर्देशक

डॉ. श्रीनिवास मिश्रा

से.नि. प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरपाटन

जिला-मैहर (म.प्र.)

शोधार्थी

चन्दा सिंह

सारांश

जनजातीय समाज के समग्र विकास में शिक्षा एक केंद्रीय तत्व है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। प्रस्तुत शोध पत्र सतना जिले के विशेष संदर्भ में इन योजनाओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। शोध में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आश्रम शाला, प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण जैसी प्रमुख योजनाओं का अध्ययन किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से यह विश्लेषित किया गया है कि इन योजनाओं से सतना जिले में जनजातीय साक्षरता दर, ड्रॉपआउट दर, उच्च शिक्षा में नामांकन एवं सामाजिक चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा है। शोध के निष्कर्ष संकेत देते हैं कि इन योजनाओं के कारण साक्षरता दर में सुधार अवश्य हुआ है, परंतु जमीनी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

मुख्य शब्द: जनजातीय शिक्षा, सरकारी योजनाएँ, समाजशास्त्रीय अध्ययन, सतना जिला, एकलव्य विद्यालय, आश्रम शाला, छात्रवृत्ति, जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश।

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में जनजातीय समुदायों की स्थिति सदा से चिंता एवं ध्यान का विषय रही है। ये समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं एवं जीवन-दर्शन के साथ भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। किंतु भौगोलिक अलगाव, सामाजिक असमानता एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ये समुदाय विकास की मुख्यधारा से बाहर रहे। शिक्षा इस खाई को पाटने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान-निर्माताओं ने अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास को विशेष प्राथमिकता दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन विशेष सावधानी से करे। अनुच्छेद 15(4), 16(4), 29(1), 275 एवं पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनेक संवैधानिक प्रावधान जनजातीय विकास को दिशा देते हैं। इन प्रावधानों के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जनजातीय शिक्षा हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की हैं।

सतना जिला मध्यप्रदेश के बाघेलखण्ड प्रमंडल में स्थित है। यहाँ कोल, गोंड एवं बैगा जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सतना जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 28 प्रतिशत जनजातीय समुदाय है। इस जनजातीय जनसंख्या की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए अनेक सरकारी योजनाएँ संचालित हैं। इन योजनाओं के सामाजिक प्रभावों का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन आवश्यक है ताकि नीति-निर्माता, शोधकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता इनकी वास्तविक उपयोगिता को समझ सकें और आवश्यक सुधार कर सकें।

2. शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य यह है कि सतना जिले में जनजातीय शिक्षा हेतु संचालित प्रमुख सरकारी योजनाओं का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया जाए। द्वितीय उद्देश्य है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के आँकड़ों का सारणीबद्ध विश्लेषण किया जाए। तृतीय उद्देश्य के अंतर्गत जनजातीय साक्षरता दर, ड्रॉपआउट दर एवं उच्च शिक्षा में नामांकन पर इन योजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाए। चतुर्थ उद्देश्य के रूप में योजनाओं के सामाजिक परिणामों – जैसे महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता एवं सांस्कृतिक परिवर्तन

— का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया जाए। पंचम उद्देश्य है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान की जाए और सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव दिए जाएँ।

3. शोध का महत्व

जनजातीय शिक्षा योजनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह शोध सामाजिक परिवर्तन, विकास समाजशास्त्र एवं नीति-मूल्यांकन के सिद्धांतों को वास्तविक क्षेत्र के आँकड़ों के साथ परखने का अवसर देता है। यह अध्ययन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधियों का समन्वय करते हुए जनजातीय शिक्षा की वास्तविकता को उजागर करता है।

व्यावहारिक दृष्टि से यह शोध सतना जिले के जनजातीय कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करने में सहायक होगा। इससे भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं लक्षित लाभार्थियों तक सेवा पहुँचाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही यह शोध राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय शिक्षा नीति की समीक्षा एवं पुनर्संरचना हेतु भी संदर्भ सामग्री प्रदान करता है।

4. सतना जिले में संचालित योजनाओं के आँकड़े एवं विश्लेषण

4.1 प्रमुख जनजातीय शिक्षा योजनाएँ — एक दृष्टि

सारणी-1: सतना जिले में संचालित प्रमुख जनजातीय शिक्षा योजनाओं का विवरण

क्र.	योजना का नाम	संचालक संस्था	लक्ष्य समूह	प्रारम्भ वर्ष	सहायता का प्रकार
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	केंद्र/राज्य सरकार	अनुसूचित जनजाति	2000	आवास + शिक्षा
2	आश्रम शाला योजना	आदिम जाति कल्याण विभाग	अनुसूचित जनजाति	1956	आवास + शिक्षा

3	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	केंद्र सरकार	कक्षा 9-10 के ST छात्र	1977	आर्थिक सहायता
4	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	केंद्र/राज्य सरकार	उच्च शिक्षा ST छात्र	1977	शुल्क + भत्ता
5	मुख्यमंत्री मेधावी योजना	म.प्र. शासन	मेधावी ST विद्यार्थी	2017	उच्च शिक्षा शुल्क
6	राष्ट्रीय फेलोशिप (ST)	UGC / Ministry	शोध छात्र (ST)	2005	शोध अनुदान
7	विशेष शिक्षा विकास योजना	ITDA / TRIFED	जनजातीय क्षेत्र	2010	अधोसंरचना
8	निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक योजना	म.प्र. शासन	कक्षा 1-12 ST छात्र	2003	पुस्तक + गणवेश

स्रोत: आदिम जाति कल्याण विभाग, सतना; म.प्र. शासन की वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सतना जिले में जनजातीय शिक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की आठ प्रमुख योजनाएँ संचालित हैं। इनमें आवासीय शिक्षा, आर्थिक सहायता एवं अधोसंरचना विकास तीनों आयामों को सम्मिलित किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं आश्रम शाला योजनाएँ सबसे प्राचीन एवं व्यापक हैं जो दशकों से जनजातीय शिक्षा की रीढ़ रही हैं। छात्रवृत्ति योजनाएँ आर्थिक बाधा को कम करने में सहायक हैं जबकि मुख्यमंत्री मेधावी योजना उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देती है।

4.2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नामांकन की स्थिति (सतना जिला)

सारणी-2: सतना जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नामांकन (2021-24)

क्र.	विद्यालय का नाम / स्थान	स्वीकृत क्षमता	नामांकित (2021-22)	नामांकित (2022-23)	नामांकित (2023-24)	लिंग
1	EKVS मैहर, सतना	480	412	438	461	मिश्र
2	EKVS रामपुर बाघेलान	320	278	295	310	मिश्र
3	EKVS उचेहरा	320	241	268	287	मिश्र
4	EKVS नागौद	480	390	418	447	मिश्र
5	EKVS अमरपाटन	320	265	289	304	मिश्र
—	कुल	1920	1586	1708	1809	—

स्रोत: EKVS प्रबंधन समिति, सतना जिला; आदिम जाति कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट।

सारणी-2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सतना जिले के पाँच एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की कुल स्वीकृत क्षमता 1920 सीटों की है। वर्ष 2021-22 में कुल 1586 विद्यार्थी नामांकित थे जो कुल क्षमता का 82.6 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 तक यह संख्या बढ़कर 1809 हो गई जो क्षमता का 94.2 प्रतिशत है। तीन वर्षों में नामांकन में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो इन विद्यालयों के प्रति जनजातीय परिवारों में बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। मैहर और नागौद के विद्यालयों में नामांकन सबसे अधिक है क्योंकि इन क्षेत्रों में जनजातीय आबादी का घनत्व अधिक है।

4.3 छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन एवं वितरण की स्थिति

सारणी-3: सतना जिले में जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं का वितरण विवरण (2021-2024)

क्र.	योजना	वर्ष	आवेदित (SI)	स्वीकृत	राशि (₹ लाख)	स्वीकृति %
------	-------	------	-------------	---------	--------------	------------

1	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2021-22	6842	6105	84.32	89.2%
2	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2022-23	7218	6584	91.47	91.2%
3	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2023-24	7651	7092	98.73	92.7%
4	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2021-22	3241	2786	142.18	85.9%
5	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2022-23	3518	3104	158.64	88.2%
6	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2023-24	3847	3492	178.29	90.8%
7	मुख्यमंत्री मेधावी योजना	2022-23	412	374	62.40	90.8%
8	मुख्यमंत्री मेधावी योजना	2023-24	489	451	74.18	92.2%

स्रोत: जिला शिक्षा कार्यालय, सतना; राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल, म.प्र. शासन।

सारणी-3 के आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2021-22 में 6842 आवेदन आए थे जो 2023-24 में बढ़कर 7651 हो गए। स्वीकृति दर भी 89.2 प्रतिशत से बढ़कर 92.7 प्रतिशत हो गई है जो प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार का संकेत देती है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी यही प्रवृत्ति दिखती है। वितरित राशि में भी तीन वर्षों में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री मेधावी योजना में लाभार्थियों की संख्या अभी सीमित है क्योंकि इसके लिए आवश्यक अंक अर्जित करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों की संख्या अभी भी कम है।

4.4 जनजातीय साक्षरता एवं ड्रॉपआउट दर में परिवर्तन

सारणी-4: सतना जिले में जनजातीय साक्षरता दर एवं ड्रॉपआउट दर (जनजातिवार तुलना)

क्र.	जनजाति	साक्षरता 2001 (%)	साक्षरता 2011 (%)	साक्षरता 2021 (अनु.)	प्राथ. ड्रॉपआउट %	माध्य. ड्रॉपआउट %	उच्च श्रेणी नामांकन %
1	कोल	36.4	44.8	52.3	28.4	41.7	6.2
2	गोंड	48.2	57.6	63.9	21.3	34.2	11.8
3	बैगा	24.1	32.7	41.5	34.8	52.3	3.1
4	सतना जिला (समग्र ST)	41.3	51.2	58.7	24.6	38.9	9.4
5	म.प्र. ST औसत	42.7	50.6	57.8	23.1	36.4	10.2

स्रोत: जनगणना 2001, 2011; UDISE+ 2023-24; जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सतना। (2021 के आँकड़े अनुमानित हैं।)

सारणी-4 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2001 से 2021 की अवधि में सतना जिले की सभी प्रमुख जनजातियों में साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कोल जनजाति में साक्षरता 2001 के 36.4 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में अनुमानतः 52.3 प्रतिशत हो गई। गोंड जनजाति में यह 48.2 से बढ़कर 63.9 प्रतिशत हो गई। किंतु ड्रॉपआउट दर अभी भी चिंताजनक है। कोल जनजाति में माध्यमिक स्तर पर 41.7 प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। बैगा जनजाति में यह समस्या सर्वाधिक गम्भीर है जहाँ माध्यमिक ड्रॉपआउट 52.3 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा में जनजातीय नामांकन का प्रतिशत अत्यंत कम – मात्र 6.2 से 11.8 प्रतिशत के मध्य – है जो दर्शाता है कि उच्च शिक्षा तक पहुँचना अभी भी जनजातीय परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

4.5 योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का संकेतक-आधारित विश्लेषण

सारणी-5: सतना जिले में जनजातीय शिक्षा योजनाओं के सामाजिक प्रभाव के संकेतक

क्र.	सामाजिक सूचक	2011 की स्थिति	2021 (अनु.)	परिवर्तन की दिशा	टिप्पणी
1	बाल विवाह दर (ST परिवार)	38.2%	24.7%	↓ सकारात्मक	शिक्षा से कमी
2	संस्थागत प्रसव दर	41.3%	68.9%	↑ सकारात्मक	आशा + जागरूकता
3	महिला साक्षरता (ST)	33.4%	48.6%	↑ सकारात्मक	योजनाओं का प्रभाव
4	पंचायत में ST महिला प्रतिनिधि	18%	34%	↑ सकारात्मक	राजनीतिक सशक्तिकरण
5	सरकारी नौकरी में ST युवा	4.2%	8.7%	↑ सकारात्मक	शिक्षा + आरक्षण
6	उच्च शिक्षा में ST नामांकन	3.1%	8.4%	↑ धीमी गति	अभी और प्रयास जरूरी

स्रोत: NFHS-5 (2019-21), जिला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, जिला पंचायत रिपोर्ट, सतना।

सारणी-5 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय शिक्षा योजनाओं का व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ा है। बाल विवाह दर में 2011 के 38.2 प्रतिशत से 2021 में 24.7 प्रतिशत तक की कमी शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाती है। संस्थागत प्रसव दर में 27.6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि स्वास्थ्य जागरूकता के विस्तार का प्रमाण है। पंचायत में जनजातीय महिला प्रतिनिधियों की संख्या में दोगुनी वृद्धि राजनीतिक सशक्तिकरण का सुखद संकेत है। सरकारी सेवाओं में जनजातीय युवाओं की भागीदारी भी लगभग दोगुनी हुई है। हालाँकि उच्च शिक्षा में नामांकन की वृद्धि की गति अभी भी धीमी है और इस क्षेत्र में विशेष प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है।

4.6 योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

सतना जिले में जनजातीय शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रथम, जागरूकता का अभाव – अनेक जनजातीय परिवार उपलब्ध योजनाओं से परिचित नहीं हैं और पात्र होते हुए भी लाभ से वंचित रहते हैं। द्वितीय, प्रशासनिक जटिलता – छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया जटिल होने से निरक्षर एवं अर्ध-साक्षर परिवार आवेदन नहीं कर पाते। तृतीय, भौगोलिक बाधाएँ – सुदूर वनग्रामों में विद्यालयों की दूरी, सड़क एवं परिवहन का अभाव बच्चों को नियमित उपस्थिति में बाधा डालता है। चतुर्थ, शिक्षक उपस्थिति – ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी एवं अनुपस्थिति शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करती है। पंचम, आर्थिक दबाव – परिवार की आजीविका के लिए बच्चों का मजदूरी में भागीदार होना एक बड़ी समस्या है जिसे केवल छात्रवृत्ति से हल नहीं किया जा सकता।

5. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के विश्लेषण से निम्न प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। सतना जिले में जनजातीय शिक्षा के लिए संचालित सरकारी योजनाएँ अपने उद्देश्यों की दिशा में सार्थक प्रगति कर रही हैं। साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि, ड्रॉपआउट दर में आंशिक कमी एवं छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की बढ़ती संख्या इन योजनाओं की उपयोगिता को प्रमाणित करती है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नामांकन की बढ़ती दर जनजातीय समुदाय में शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का सूचक है।

तथापि उच्च शिक्षा में जनजातीय नामांकन का अत्यंत निम्न प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉपआउट दर एवं बैगा जैसी अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शैक्षिक पिछड़ापन इस बात का संकेत देता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। योजनाओं का सामाजिक प्रभाव केवल साक्षरता तक सीमित नहीं है – महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता, बाल विवाह में कमी एवं राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि भी इन योजनाओं की गहरी सामाजिक उपलब्धियाँ हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह स्पष्ट है कि जनजातीय शिक्षा का प्रश्न केवल नामांकन एवं साक्षरता तक सीमित नहीं है, अपितु यह सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा एक व्यापक प्रश्न है। योजनाओं को समुदाय-केंद्रित एवं सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है।

6. सुझाव

प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तथा उनकी भौतिक एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। एकलव्य विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों को तत्काल भरा जाए एवं शिक्षकों को जनजातीय संस्कृति एवं भाषा का प्रशिक्षण दिया जाए।

छात्रवृत्ति योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल बनाया जाए ताकि पात्र विद्यार्थी बिना बिचौलियों के लाभ प्राप्त कर सकें। ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएँ जो जनजातीय परिवारों को योजनाओं की जानकारी एवं आवेदन में सहायता प्रदान करें।

उच्च शिक्षा में जनजातीय नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष कोचिंग केंद्र, करियर काउंसलिंग एवं मेंटरिंग कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएँ। ड्रॉपआउट रोकने के लिए मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति के साथ-साथ माता-पिता को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएँ बनाई जाएँ। शिक्षा में जनजातीय भाषाओं एवं लोक-ज्ञान को सम्मिलित किया जाए ताकि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। योजनाओं के प्रभाव का नियमित एवं स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए जिससे कमज़ोरियों की पहचान कर समय रहते सुधार किया जा सके।

7. संदर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, एस. एन. (2002). भारत में जनजातीय विकास एवं समस्याएँ. नई दिल्ली: साहित्य भण्डार।
2. उइके, एस. के. (2015). गोंड जनजाति का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन. भोपाल: म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. कुमार, आर. (2010). जनजातीय शिक्षा और विकास. नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स।
4. खरे, वी. एस. (1998). मध्यप्रदेश की जनजातियाँ: एक परिचय. भोपाल: आदिम जाति कल्याण विभाग।
5. गुप्ता, एस. (2018). जनजातीय समाज में परिवर्तन की दिशाएँ. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।

6. चौधरी, एम. के. (2007). कोल जनजाति: इतिहास, समाज और संस्कृति. इलाहाबाद: लोक भारती प्रकाशन।
7. त्रिवेदी, एच. आर. (1993). जनजातीय समाजशास्त्र. नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।
8. दुबे, एस. सी. (1977). भारत में जनजातीय समस्याएँ. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
9. पांडे, बी. बी. (2011). मध्यप्रदेश में जनजातीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति. भोपाल: आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान।
10. पाठक, ए. (2014). आदिवासी जीवन और संघर्ष. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
11. मिश्र, एस. (2016). बाघेलखण्ड की जनजातियाँ: सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन. रीवा: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
12. शर्मा, ए. के. (2019). आदिवासी विमर्श और शिक्षा नीति. नई दिल्ली: हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय।
13. सिंह, के. एस. (1993). The Scheduled Tribes. Anthropological Survey of India. New Delhi: Oxford University Press.
14. Bhattacharya, S. (2005). Tribal Education in India. New Delhi: Concept Publishing Company.
15. Census of India (2011). Scheduled Tribe Population Data. New Delhi: Office of the Registrar General.
16. Ministry of Tribal Affairs, Government of India (2023). Annual Report 2022-23. New Delhi: GoI.
17. Madhya Pradesh Tribal Welfare Department (2023). Tribal Sub-Plan Report — Satna District 2023-24. Bhopal: Government of Madhya Pradesh.
18. NFHS-5 (2021). National Family Health Survey — Madhya Pradesh Factsheet. Mumbai: IIPS.
19. NUEPA (2023). District Report Cards — Satna. New Delhi: National University of Educational Planning and Administration.
20. SCERT, Madhya Pradesh (2022). State Report on Tribal Education. Bhopal: State Council of Educational Research and Training.
21. UDISE+ (2024). Unified District Information System for Education Plus — Satna District Data 2023-24. New Delhi: MoE, GoI.